

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 2993  
दिनांक 07 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

.....  
**नदियों का संरक्षण और शुद्धिकरण**

**2993. श्री मलविंदर सिंह कंग:**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश की प्रमुख नदियों के संरक्षण और शुद्धिकरण की योजना शुरू की है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है तथा इस योजना के अंतर्गत कितनी नदियों को शामिल किया गया है; और
- (ग) उक्त योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री**

**(श्री राज भूषण चौधरी)**

**(क) से (ग):** राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और स्थानीय निकायों की यह प्राथमिक ज़िम्मेदारी है कि वे सीवेज और औद्योगिक अपशिष्टों को प्राप्तकर्ता जल निकायों या भूमि में छोड़ने से पहले, प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण हेतु इनका आवश्यक उपचार सुनिश्चित करें। मंत्रालय गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबंधन के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) देश में गंगा और उसकी सहायक नदियों के अलावा अन्य नदियों के संरक्षण और उनमें प्रदूषण निवारण का कार्य करता है।

नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत, गंगा बेसिन की कुल 31 नदियों को प्रदूषण निवारण हेतु शामिल किया गया है। 212 सीवरेज अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें लगभग 5,220 किलोमीटर लम्बे सीवर नेटवर्क को बिछाना और 6,540 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) सीवेज उपचार क्षमता का सृजन शामिल है। इनमें से 136 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं, जिसके परिणामस्वरूप 3,781 एमएलडी सीवेज उपचार क्षमता का सृजन और पुनर्वास हुआ है। एनआरसीपी ने अब तक देश के 17 राज्यों की 57 नदियों को 4378 करोड़ रुपये की लागत से कवर किया है और चिन्हित शहरों में कुल 2,945 एमएलडी सीवेज उपचार क्षमता का सृजन किया गया है।

इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), स्मार्ट सिटी मिशन और स्वच्छ भारत मिशन - शहरी, योजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य चिन्हित कस्बों में सीवरेज अवसंरचना का सृजन और/या संवर्धन करना है एवं इस प्रकार उन कस्बों में नदियों और अन्य जल निकायों, स्वच्छता प्रणालियों और जल प्रबंधन की जल गुणवत्ता में सुधार करना है।